

माइक्रोफाइनेंस संबंधी संकट

प्रलमिस के लिये:

[माइक्रोफाइनेंस संस्थान](#), गैर-नष्पिपादति परसिंपत्तयिँ, [भारतीय रज़िर्व बैंक](#), [स्व-नयिजति महिला संघ](#), [राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक](#)

मेन्स के लिये:

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में चुनौतियिँ और सुधार, वत्तीय समावेशन एवं ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका

[स्रोत: फाईनेंशलि एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

[भारत के माइक्रोफाइनेंस संस्थान \(MFI\)](#) एक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि [सकल गैर-नष्पिपादति परसिंपत्तयिँ \(NPA\)](#) मार्च 2025 तक 16% तक बढ़ गई, जो वर्ष 2024 के 8.8% से लगभग दोगुनी हो गई है। जैसे-जैसे ऋण लौटाने में चूक बढ़ रही है, ऋणदाता इसमें रूचि नहीं दिखा रहे हैं और नियामक हस्तक्षेप से इस क्षेत्र की स्थिरता के संदर्भ में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

MFI में NPA में वृद्धि के लिये कौन-से कारक ज़िम्मेदार हैं?

- **माइक्रोफाइनेंस की चक्रीय प्रकृति:** MFI ने पारंपरिक रूप से चक्रीय पैटर्न का पालन किया है, जिसमें प्रत्येक 3-5 वर्ष में संकट आते हैं और वर्तमान स्थिति इस ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुरूप है।
 - हालाँकि, आर्थिक मंदी (वर्ष 2024-25 में GDP 4 वर्ष की तुलना में 6.4% से नचिले स्तर पर), प्राकृतिक आपदाओं (हीट वेव, बाढ़) और चुनाव संबंधी व्यवधानों से प्रेरित ऋण चूक में वृद्धि जैसे गहरे संरचनात्मक मुद्दों ने उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता को प्रभावित किया।
- **उधारकर्ताओं का अत्यधिक ऋणग्रस्त होना:** तेज़ी से वसति करने के प्रयास में, MFI ने पहले से ही उच्च स्तर के ऋणग्रस्त उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करना शुरू कर दिया है। इससे ग्राहक आधार पर अत्यधिक ऋणग्रस्तता उत्पन्न हो गई है, जो पुनर्भुगतान करने में असमर्थ है।
 - कई MFI ने उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता का मूल्यांकन करने में नमी बरती है तथा व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बजाय मात्रा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।
- **उधारकर्ता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अक्सर कई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MFI) तथा अन्य स्रोतों से ऋण लेते हैं, जिससे उनका ऋण बोझ बढ़ जाता है तथा ऋण न चुकाने की संभावना बढ़ जाती है।**
- **क्रेडिट कार्ड बकाया में वर्ष 2023 में 2.30 लाख करोड़ रुपए से वर्ष 2024 में 2.71 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि, बढ़ते उपभोक्ता ऋण की व्यापक प्रवृत्ति को उजागर करती है।**
- **संयुक्त देयता समूह (JLG) मॉडल का कमज़ोर होना:** माइक्रोफाइनेंस पर्यायों के लिये केंद्रीय JLG मॉडल, ऋण चुकौती के लिये सामाजिक दबाव और सामूहिक ज़िम्मेदारी पर निर्भर करता है।
- हालाँकि, उधारकर्ताओं के बदलते प्रोफाइल, कमज़ोर समूह सामंजस्य और बढ़ती व्यक्तिगत चूक के कारण यह कम प्रभावी होता जा रहा है।
- **बढ़ता वनियामक दबाव:** भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने ऋण देने के लिये सख्त मानदंड और प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे कठोरतामक ऋण देने की प्रथाओं पर अंकुश लगाना। हालाँकि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य इस क्षेत्र को स्थिर करना है, लेकिन इनसे MFI के लिये अल्पकालिक तरलता संकट भी उत्पन्न हो गया है।
 - राज्य सरकारों ने माइक्रोफाइनेंस उधारदाताओं द्वारा दबावपूर्ण वसूली विधियों को रोकने के लिये कानून बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें अननुपालन करने पर कठोर दंड भी निर्धारित किये गए हैं।
 - उदाहरण के लिये, तमिलनाडु विधानसभा ने मनी लेंडिंग एंटीटीज़ (दबावपूर्ण क्रियावली की रोकथाम) अधिनियम पारित किया, जबकि कर्नाटक ने उधारकर्ताओं को अनुचित कठिनाई पहुँचाने वाले उधारदाताओं के लिये कठोर दंड का प्रस्ताव रखा।
 - इसके अतिरिक्त, **करज़ मुक्त अभियान जैसे अभियानों (ऋण माफी योजनाएँ)** ने पुनर्भुगतान की संस्कृति को कमज़ोर किया है, क्योंकि उधारकर्ता सरकार से ऋण माफी की उम्मीद करते हैं, जिससे डफ़ॉल्ट की दर में वृद्धि होती है।

माइक्रोफाइनेंस क्या है?

- **माइक्रोफाइनेंस:** माइक्रोफाइनेंस, जिसे माइक्रोक्रेडिट भी कहा जाता है, वित्तीय सेवाओं की प्रदानगी को संदर्भित करता है, जैसे कि छोटे ऋण, बचत खाते, बीमा और धन अंतरण, जो विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा से वंचित जनसंख्याओं को प्रदान की जाती हैं।
 - इसका उद्देश्य हाशिये पर रहने वाली और कम आय वाली समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं, को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना है।
- **माइक्रोफाइनेंस का महत्त्व:** यह आय-उत्पादक गतिविधियों के लिये वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके गरीबी घटाने का एक उपकरण है।
 - माइक्रोफाइनेंस छोटे पैमाने के व्यवसायों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, का समर्थन करता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और रोजगार को बढ़ावा देता है।
 - पछिले तीन दशकों में, इसने भारत के लगभग 100 मिलियन ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार किया है।
 - माइक्रोफाइनेंस महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाकर लिंग समानता को बढ़ावा देता है।
 - वर्ष 2022-23 में, भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने **80 लाख नई महिला ग्राहकों** को जोड़ा, जिससे वर्ष 2023 तक कुल 6.64 करोड़ महिलाएँ और 12.96 करोड़ सक्रिय ऋण हो गए, जैसा कि **इंडिया माइक्रोफाइनेंस रिव्यू FY23 रिपोर्ट** में बताया गया है।
- **भारत में माइक्रोफाइनेंस:** भारत में माइक्रोफाइनेंस की शुरुआत वर्ष 1974 में गुजरात में **स्व-नरिमति महिला संघ (SEWA)** बैंक की स्थापना से हुई, जिसका उद्देश्य कम आय वाली महिलाओं को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना था, जो औपचारिक बैंकों से बाहर थीं।
 - वर्ष 1992 में, **नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD)** ने **स्व-सहायता समूह (SHG)-बैंक लिंकिज प्रोग्राम** की शुरुआत की, जिससे महिलाओं के लिये छोटे पैमाने पर बचत और ऋण तक पहुँच में सुधार हुआ।
 - वर्ष 2011 में, भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी, जिससे माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं (MFI) को नीतिसमर्थन प्राप्त हुआ।
 - हालाँकि, वर्ष 2010 में आंध्र प्रदेश में माइक्रोफाइनेंस संकट, जो आक्रामक उधारी प्रथाओं के कारण उत्पन्न हुआ, ने बढ़ती नगिरानी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं (NBFC-MFI) को नियंत्रित करने के लिये मालेगाम समिति (2010) के गठन को प्रेरित किया।
 - वर्ष 2015 में, **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)** के तहत मुद्रा बैंक की स्थापना ने छोटे, गैर-कॉर्पोरेट उद्यमों को क्रेडिट प्रदान करके माइक्रोफाइनेंस पारस्थितिकी तंत्र को और मज़बूत किया।
- **भारत में माइक्रोफाइनेंस की वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ भारत के 28 राज्यों, 8 केंद्रशासित प्रदेशों और 730 ज़िलों में कार्यरत हैं।
 - माइक्रोफाइनेंस उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 16% की वृद्धि की, जबकि वर्ष 2022-23 में यह वृद्धि 21% थी। मार्च 2024 तक, इस क्षेत्र का संयुक्त पोर्टफोलियो 4.08 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया।
 - वर्ष 2024 तक, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में सबसे अधिक बकाया ऋण वाले शीर्ष पाँच राज्य **बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल** हैं। ये राज्य मलिकर उद्योग के कुल पोर्टफोलियो का लगभग 58% हिस्सा बनाते हैं।

सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI)

परिचय:

- वित्तीय सेवाएँ और छोटे मूल्य के ऋण प्रदान करता है
- लक्ष्य - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम आय वाले परिवार, छोटे व्यवसाय और उद्यमी
- अधिकतम वार्षिक आय मानदंड - 3 लाख रुपए (संपादित-छोटे लोन हेतु)

सूक्ष्म वित्त संस्थान क्षेत्र का विकास

- प्रारंभिक काल (वर्ष 1974-1984):
 - महिलाओं के लिये श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना
 - नाबार्ड ने SHG संपर्क को बढ़ावा दिया
- परिवर्तन अवधि (वर्ष 2002-2006):
 - स्वयं सहायता समूहों के लिये असुरक्षित ऋण मानदंडों को सुरक्षित ऋणों के साथ संरेखित किया गया
 - RBI ने सूक्ष्म वित्त को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया
- विकास और संकट (वर्ष 2007-2010):
 - निजी इक्विटी निवेश → सूक्ष्म वित्त संस्थानों का तीव्र विकास
 - माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (MFIN) का गठन
- समेकन और परिपक्वता (वर्ष 2012-2015):
 - मालेगाम समिति (वर्ष 2012) ने विनियामक परिवर्तनों की सिफारिश की
 - NBFC की नवीन श्रेणी - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (NBFC-MFI)
 - बंधन बैंक (सबसे बड़ा माइक्रोलेण्डर) को RBI द्वारा यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस (वर्ष 2014)
 - मुद्रा बैंक का शुभारंभ (वर्ष 2015)



भारत में MFI को RBI द्वारा NBFC-MFI फ्रेमवर्क 2014 के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

विज्ञान मॉडल

- स्वयं सहायता समूह (SHG):
 - अनौपचारिक समूह (10-20 सदस्य) मिलकर बचत करते हैं और ऋण प्राप्त करते हैं
 - SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से बैंकों से जोड़ा गया
- सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI):
 - माइक्रो-क्रेडिट और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना
 - 4-10 सदस्यों वाले संयुक्त ऋण समूहों (JLG) के माध्यम से ऋण

MFI के प्रकार

- NGO-MFI (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1880 के तहत)
- सहकारी समितियाँ
- धारा-8 के अधीन कंपनियाँ (कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत)
- NBFC-MFIs (सूक्ष्म वित्त बाजार का 80% हिस्सा)

लाभ

- डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन
- आत्मनिर्भरता (उद्यमिता और बेहतर आजीविका)
- स्थिर आय (संपत्ति निर्माण)
- महिला उद्यमिता



MFI की चुनौतियाँ	आगे की राह
उच्च व्याज दरें	विनियामक निरीक्षण में सुधार करना और व्याज दर सीमा को बढ़ाना।
ऋण कर्तव्यों का अति-ऋणग्रस्त होना	ऋण जोखिम मूल्यांकन को सुदृढ़ करना और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना।
बाह्य वित्तपोषण पर निर्भरता	साझेदारी और पूंजी बाजार के माध्यम से वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाना।
ऋणकर्तव्यों में वित्तीय साक्षरता न्यून होना	वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों/अभियानों को बढ़ावा देना



माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ संकट का समाधान कैसे कर सकती हैं और दीर्घकालिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं?

- समग्र त्रस्तितरीय मॉडल अपनाना: MFI [?] जैसे समग्र मॉडल को अपनाना चाहिये जो आजीविका संवर्धन, वित्तीय सेवाओं और संस्थागत विकास को एकीकृत करता है।
- यह कौशल प्रशिक्षण, बाज़ार संपर्क और बीमा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि केवल ऋण मॉडल में अनुपस्थिति प्रमुख तत्त्व हैं।
 - त्रस्तितरीय मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि सूक्ष्म ऋणों का उपयोग आय-उत्पादक गतिविधियों के लिये किया जाए न कि गैर-उत्पादक उद्देश्यों के लिये, जिससे अति-ऋणग्रस्तता को रोकने और वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।
- क्रेडिट रेटिंग में सुधार: केवल पुनर्भुगतान दरों और पोर्टफोलियो वृद्धि के बजाय आर्थिक स्थिरता तथा घरेलू आय में सुधार जैसे परिणामों को प्राथमिकता देकर क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली में सुधार करना चाहिये।
 - यह बदलाव यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय संस्थाएँ न केवल वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनी रहें, बल्कि उधारकर्ताओं के जीवन में भी सार्थक योगदान दें।
- व्यक्तिगत ऋण मूल्यांकन की ओर बदलाव: समूह-आधारित JLG मॉडल से हटकर व्यक्तिगत ऋण मूल्यांकन शुरू करने से NPA में कमी आ सकती है।
- जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग: वास्तविक समय डेटा ट्रैकिंग, अपने ग्राहक को जानें (KYC) सत्यापन तथा ओपन API के माध्यम से एंड-टू-एंड ऋण उत्पत्ति प्रणाली (LOS), ऋण प्रबंधन प्रणाली (LMS) जैसे सुरक्षा ऋण प्रबंधन प्लेटफार्मों को अपनाने से सेवा वितरण में काफी सुधार होगा।
 - बड़े डेटा एनालिटिक्स को अपनाने से जोखिम मूल्यांकन में सुधार हो सकता है और ऋण अंडरराइटिंग में सुधार हो सकता है, जिससे संभावित रूप से चूक में कमी आ सकती है।
- संग्रहण प्रथाओं में सुधार: यद्यपि बिलपूर्वक प्रथाओं को रोकने के लिये कानूनी उपाय आवश्यक हैं, MFI को ग्राहक संबंधों और संग्रहण रणनीतियों में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
 - ऋणकर्ताओं को धमकी देने के बजाय संचार और समर्थन सेवाओं के माध्यम से जोड़ना विश्वास बना सकता है तथा पुनर्भुगतान दरों में सुधार कर सकता है।
 - आय-आधारित पुनर्भुगतान जैसे अनुकूल ऋण उत्पाद उपलब्ध कराने से उधारकर्ताओं को अपने पुनर्भुगतान को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सहायता मिल सकती है।
- वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना: उधारकर्ताओं के लिये वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम उन्हें ऋण न चुकाने के परिणामों को समझने और ऋण प्रबंधन की उनकी क्षमता में सुधार करने में सहायता कर सकते हैं।

नबिर्कष

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में NPA में वृद्धि एक चुनौतीपूर्ण लेकिन चक्रीय चरण का संकेत देती है जो प्रणालीगत संघर्षों के बजाय आंतरिक गलतियों से प्रेरित है। SBI जैसे प्रमुख ऋणदाताओं द्वारा इस क्षेत्र का समर्थन जारी रखने और बेहतर प्रशासन के लिये दबाव डालने के साथ, इस क्षेत्र का अनुकूलन आत्म-सुधार, नियामक अनुशासन तथा नरितर संस्थागत समर्थन पर नरिभर करेगा। सुधार का रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन सामूहिक प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है।

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]

प्रश्न: “माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के बीच गैर-नबिषादित परसिंपत्तियों में वृद्धि भारत के ग्रामीण ऋण वितरण मॉडल में गहरे संरचनात्मक मुद्दों को दर्शाती है।” आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]

प्रश्न. माइक्रोफाइनेंस कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। इसमें उपभोक्ता और स्वरोज़गार करने वाले दोनों शामिल हैं। माइक्रोफाइनेंस के तहत दी जाने वाली सेवा/सेवाएँ हैं (2011)

1. ऋण सुवधिएँ
2. बचत सुवधिएँ
3. बीमा सुवधिएँ
4. फंड ट्रांसफर सुवधिएँ

सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

- (b) केवल 1 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न: महिला स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करने से लैंगिक असमानता, नरिधनता एवं कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ने में कसि प्रकार सहायता मलि सकती है? उदाहरण सहति समझाइये। (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/stress-in-microfinance>

